छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग

शिक्षा संजीवनी अभियान के नाम पर गुमराह करने के विरोध में एनएसयूआई का कलेक्ट्रेट घेराव आज

» बदहाल शिक्षा व्यवस्था और पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज के विरोध में छात्र-युवा करेंगे प्रदर्शन

पीपुल्स प्रवक्ता बैतूल।

छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से तत्काल कराने की मांग और शिक्षा संजीवनी अभियान के नाम पर विद्यार्थियों को गुमराह करने के विरोध में एनएसयूआई आज कलेक्ट्रेट घेराव करेगी। जिले की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज के विरोध सहित विद्यार्थियों एवं युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन की तैयारी की है। 3 सितंबर को दोपहर 1ः30 बजे शिवाजी ऑडिटोरियम के पास छात्र-युवा एकत्र होंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से तत्काल कराने की मांग को प्रमुखता से उठाएगी।

संगठन का कहना है कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं लोकतांत्रिक तरीके से उठाने का प्रभावी मंच नहीं मिल रहा है। वहीं शिक्षा संजीवनी अभियान के नाम पर विद्यार्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संगठन शिक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार की मांग करेगा।

प्रदर्शन में पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज के स्थान पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, भीमपुर और शाहपुर की शासकीय आईटीआई का निजीकरण कर परम फाउंडेशन को नहीं सौंपने, बीएड एवं डीएड कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली पर रोक और जिले के सभी कॉलेजों की मान्यता एवं संचालन की आवश्यक शर्तों की जांच की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला स्तरीय अध्ययन केंद्र, बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष रोजगार अभियान, सरकारी छात्रावासों की उच्चस्तरीय जांच, ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा बढ़ाने, खेल सुविधाओं का विस्तार और विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए विशेष जनसुनवाई शुरू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रहेगी। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रोहन ठाकुर ने विद्यार्थियों और युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में शिवाजी ऑडिटोरियम के पास पहुंचकर प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। संगठन ने मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी दी है।

96 प्रतिशत अंक लेकर जिले में टॉप करने वाले अभिषेक को सीएम ने लैपटॉप देकर किया सम्मानित

पीपुल्स प्रवक्ता बैतूल।

कक्षा 12वीं में 96 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल के छात्र अभिषेक नागले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लैपटॉप देकर सम्मानित किया। भोपाल में 1 सितंबर को आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में अभिषेक को यह सम्मान मिला। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लेकर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 सितंबर को मिनटो हाल के सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभिषेक नागले को लैपटॉप सौंपकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अभिषेक ने कक्षा 12वीं में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर बैतूल जिले में टॉप किया था। अभिषेक नागले की इस उपलब्धि से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल का भी गौरव बढ़ा है। उनकी सफलता पर परिवार और विद्यालय में खुशी का माहौल है। अभिषेक लाइफ लाइन बडोरा, बैतूल निवासी एडवोकेट दिनेश कुमार नागले के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने पर अभिषेक ने अपनी उपलब्धि से जिले का नाम भी गौरवान्वित किया है।

शिकायत के बावजूद यात्री प्रतीक्षालय से नहीं हटा अतिक्रमण

महीनों पहले एसडीएम को दिया आवेदन स्थिति जस की तस अब कलेक्टर से शिकायत

पीपुल्स प्रवक्ता बैतूल।

आमला तहसील के ग्राम बम्हनी पंखा में मुलताई-बोरदेही मुख्य मार्ग पर स्थित शासकीय यात्री प्रतीक्षालय से अतिक्रमण महीनों बाद भी नहीं हटाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतीक्षालय पर दुकानों के संचालन की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी आमला से की गई थी, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आने और मामले को लेकर खबरें प्रकाशित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने 2 सितंबर को कलेक्टर बैतूल से फिर शिकायत की। ग्रामीणों के अनुसार, सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय के हिस्से में अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही हैं। इससे बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिलती। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को होती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रतीक्षालय परिसर में सुबह से शाम तक शराबखोरी और अभद्र भाषा के प्रयोग की स्थिति भी बनी रहती है, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को असहजता का सामना करना पड़ता है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की जांच कर प्रतीक्षालय का मौके पर निरीक्षण कराया जाए और यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार उसे हटाया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय राशि से बनाई गई सार्वजनिक सुविधा का मूल उद्देश्य यात्रियों को सुविधा देना है। इसलिए प्रतीक्षालय को अतिक्रमण से मुक्त कर यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन को लेकर आयोग ने अधिकारियों-कर्मचारियों से मांगे सुझाव

पीपुल्स प्रवक्ता जबलपुर।

मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक बुधवार को तहसील कार्यालय गोरखपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुनर्गठन आयोग के सचिव श्री अक्षय कुमार सिंह ने की।

इस दौरान प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की आवश्यकता, प्रशासनिक सुधार और आमजन तक शासकीय सेवाओं की बेहतर पहुंच सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। श्री अक्षय कुमार सिंह ने प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुगम और जनहितैषी बनाने के लिए फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के अनुभव और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उपस्थित फील्ड स्तरीय कर्मचारियों से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुधार के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय राजस्?व अधिकारी गोरखपुर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व विभिन्न विभागों के फील्ड स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

खिरिया वार्ड में जलभराव से मिलेगी बड़ी राहत, वर्षों पुरानी जल निकासी की समस्या का हुआ समाधान

झांसी रेलवे क्रॉसिंग के पास भी 450 मीटर नाले का काम पूरा 7 नपाध्यक्ष लता सकवार, सीएमओ और पार्षद प्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण

पुलिस थाने से आगासौद रोड तक 500 मीटर नाला तैयार

पीपुल्स प्रवक्ता बीना।

खिरिया वार्ड के रहवासियों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से चली आ रही जल निकासी और बरसात में जलभराव की समस्या के समाधान की दिशा में नगरपालिका द्वारा कराया गया नाला निर्माण कार्य पूरा हो गया है। नाला तैयार होने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार ने मौके पर पहुंचकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और नाले की गुणवत्ता एवं जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया।

500 मीटर लंबे नाले पर खर्च हुए 82.14 लाख रुपए: खिरिया वार्ड में पुलिस थाने से आगासौद रोड तक करीब 500 मीटर लंबाई में नाले का निर्माण कराया गया है। इस कार्य पर लगभग 82.14 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं, झांसी रेलवे क्रॉसिंग के पास करीब 450 मीटर लंबे नाले का निर्माण लगभग 71.50 लाख रुपए की लागत से पूरा कराया गया है। दोनों नालों के निर्माण से क्षेत्र में बरसात के दौरान जमा होने वाले पानी की निकासी को बेहतर व्यवस्था मिलने की उम्मीद है।

नपाध्यक्ष और सीएमओ ने परखी निर्माण की गुणवत्ता: निरीक्षण के दौरान नपाध्यक्ष लता सकवार और सीएमओ ने नाले की फिनिशिंग, ढलान और जल प्रवाह का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यह भी देखा कि पानी की निकासी में कहीं रुकावट तो नहीं आ रही है। निर्माण कार्य की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए बरसात के दौरान जल निकासी सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया गया।

सफाई के लिए जगह-जगह बनाए गए ब्लॉक: नाले में कचरा जमा होने से जल प्रवाह बाधित न हो, इसके लिए सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जगह-जगह ब्लॉक बनाए गए हैं। इन स्थानों के माध्यम से समय-समय पर नाले की सफाई की जा सकेगी और बरसात के दौरान पानी के बहाव में रुकावट की संभावना कम होगी।

कीचड़ और जलभराव से मिलेगी निजात: नाला निर्माण पूरा होने से खिरिया वार्ड और आसपास के रहवासियों को बरसात में होने वाले जलभराव, कीचड़ और जल निकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। वर्षों से परेशान रहवासियों के लिए यह निर्माण कार्य बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। स्थानीय नागरिकों ने नाला निर्माण पूरा होने पर नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि भविष्य में भी क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी।

निरीक्षण के दौरान ये रहे मौजूद: निरीक्षण के दौरान स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि विकास राजपूत, शास्त्री वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हरिओम चौबे सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे।

प्रत्येक मदिरा दुकान पर रेट लिस्ट और क्यूआर कोड लगाया जाना सुनिश्चित करें

पीपुल्स प्रवक्ता जबलपुर।

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले की प्रत्येक मदिरा दुकान पर रेट लिस्ट और क्यूआर कोड लगाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश आबकारी अधिकारियों को दिये हैं। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में आबकारी विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने शराब के अवैध विक्रय और निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर मदिरा की बिक्री की शिकायतों पर भी कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर रविशंकर राय, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह एवं सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे भी मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में मदिरा दुकानों पर क्यूआर कोड और रेट लिस्ट लगाए जाने के संबंध में जानकारी ली। साथ ही शराब दुकानों के समीप संचालित अहातों पर की गई कार्यवाही तथा इस वर्ष आरोपित की गई पेनाल्टी और जमा राशि का भी ब्यौरा लिया। उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक पर मदिरा बेचे जाने से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेने तथा उन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री एवं अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायतों पर की जा रही कार्यवाही का असर मैदानी स्तर पर दिखाई देना चाहिए।

उन्होंने इस कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने आबकारी विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की परिक्षेत्रवार समीक्षा भी की तथा शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और आवेदक की संतुष्टि के साथ निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

विधायक निर्मला सप्रे की पहल रंग लाई: बीना को मिली 2,776 करोड़ की 4-लेन सड़क की बड़ी सौगात

शोल्डर सहित बनेगा करीब 60 मीटर चौड़ा सड़क गलियारा 7 मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक ने उठाया था फोरलेन का मुद्दा

» मेहलुहा-बीना-खिमलासा से मालथौन तक 67.116 किमी मार्ग होगा 4-लेन

राजेश बबेले

पीपुल्स प्रवक्ता बीना।

बीना विधानसभा क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मेहलुहा-बीना-खिमलासा से मालथौन तक राज्य मार्ग क्रमांक-61 के 67.116 किलोमीटर हिस्से का करीब 2,776 करोड़ रुपए की लागत से चार लेन, शोल्डर सहित निर्माण किया जाएगा। लगभग 60 मीटर चौड़े सड़क गलियारे के रूप में विकसित होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना बीना को केवल बेहतर सड़क सुविधा ही नहीं देगी, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार, व्यापार, माल परिवहन और रोजगार की संभावनाओं को भी नई गति देने वाली मानी जा रही है।

16 मई 2025 को मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र: चार लेन सड़क की यह मांग बीना विधायक अधिवक्ता निर्मला सप्रे द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही थी। विधायक ने 16 मई 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मेहलुहा चौराहा से मालथौन तक करीब 75 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन की मांग की थी। विधायक ने पत्र में क्षेत्र की बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और भविष्य में भारी वाहनों की संभावित बढ़ती आवाजाही का उल्लेख करते हुए सड़क को चार लेन किए जाने की आवश्यकता बताई थी।

रिफाइनरी विस्तार के बाद बढ़ेगा माल परिवहन: विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष बीना के बढ़ते औद्योगिक महत्व को प्रमुखता से रखा था। बीना रिफाइनरी के विस्तार के बाद पेट्रोलियम एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों के परिवहन के लिए भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा क्षेत्र में जे पी पावर प्लांट, बीना रेलवे जंक्शन और औद्योगिक क्लस्टर सहित कई औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हैं। इनके विस्तार के साथ सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए चार लेन सड़क को भविष्य की जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है।

एसएच-346 और एसएच-44 को जोड़ेगा मार्ग: मेहलुहा चौराहा, बीना और खिमलासा से मालथौन तक जाने वाला यह मार्ग क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मेहलुहा के राज्य मार्ग क्रमांक-346 को

मालथौन के राज्य मार्ग क्रमांक-44 से जोड़ता है। चार लेन मार्ग बनने के बाद बीना को प्रमुख मार्गों से बेहतर संपर्क मिलने की उम्मीद है। इससे औद्योगिक माल, कृषि उत्पाद, कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। साथ ही ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को भी बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने में सुविधा मिल सकती है।

बीना के औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आधार: सड़क परियोजना के पूरा होने के बाद बीना के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। रिफाइनरी विस्तार, औद्योगिक क्लस्टर और प्रस्तावित गतिविधियों के कारण आने वाले वर्षों में माल परिवहन की जरूरत बढ़ेगी। बेहतर सड़क संपर्क से परिवहन समय घटने, आवागमन सुगम होने और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इसका सकारात्मक असर व्यापार, उद्योग, परिवहन और स्थानीय रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है।

भारी वाहनों के दबाव से मिलेगी राहत: चार लेन और शोल्डर सहित मार्ग बनने से वर्तमान सड़क की तुलना में वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है। खासतौर पर भारी वाहनों की संख्या बढ़ने की स्थिति में चौड़ा मार्ग यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इससे यातायात के दबाव को बेहतर ढंग से संभालने के साथ दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारे से जुड़ाव होगा मजबूत: विधायक निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारे से बेहतर कनेक्टिविटी का मुद्दा भी उठाया था। चार लेन मार्ग बनने से बीना के औद्योगिक क्षेत्र को व्यापक सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिल सकती है। बीना की रेलवे कनेक्टिविटी, रिफाइनरी और औद्योगिक अधोसंरचना को देखते हुए यह परियोजना क्षेत्र को परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

सिर्फ सड़क नहीं, बीना के भविष्य की नींव':निर्मला सप्रे: परियोजना को लेकर विधायक निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीना के लिए यह केवल सड़क निर्माण की परियोजना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास की दिशा बदलने वाली महत्वपूर्ण अधोसंरचना है। 2,776 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 67.116 किलोमीटर लंबा चार लेन मार्ग बीना को सड़क कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

परियोजना की खास बातें:
लागत: करीब 2,776 करोड़ रुपए,**लंबाई:** 67.116 किलोमीटर
मार्ग: मेहलुहा-बीना-खिमलासा से मालथौन, **राज्य मार्ग:** एसएच-61,**निर्माण:**चार लेन, शोल्डर सहित।
सड़क गलियारा: करीब 60 मीटर चौड़ा, **क्रियान्वयन:** मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम **संभावित लाभ:** बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विस्तार, व्यापार, माल परिवहन और रोजगार के अवसर।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग में गति लाने के कलेक्टर ने दिये निर्देश

पीपुल्स प्रवक्ता जबलपुर।

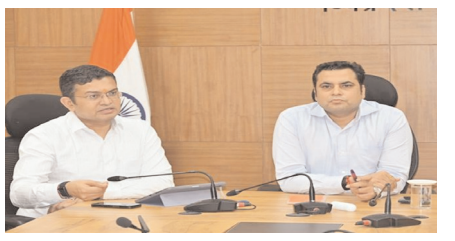

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों को 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग में गति लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग के लिए एएनएम के साथ-साथ सीएचओ को भी फील्ड विजिट पर अनिवार्य रूप से जाना होगा। कलेक्टर श्री सिंह आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। एनसीडी पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अप्रैल माह से अब तक स्क्रीनिंग की कम प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। श्री सिंह ने छूट गए लोगों की स्क्रीनिंग पीएचसी, सीएचसी और अस्पताल की ओपीडी में करने के निर्देश देते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवीन कोठारी तथा सभी विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में डायबिटीज, कैंसर स्क्रीनिंग, एनीमिया, मातृ स्वास्थ्य और डिलीवरी सेवाओं की संस्था-वार प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही आभा आईडी से लिंक कर उपचार करा रहे हाइपरटेंशन और डायबिटीज मरीजों के मामले की जानकारी दी गई। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों के तबादले की स्थिति में नए कर्मचारियों की पोर्टल आईडी तत्काल असाइन की जाए, जिससे निष्क्रिय आईडी के कारण वास्तविक डेटा प्रभावित न हो। कलेक्टर श्री सिंह ने सब-हेल्थ सेंटरों में एएनएम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से पूरे सिस्टम का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम न करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी बदलकर दूसरे कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाए। बैठक में बताया गया कि कैंसर स्क्रीनिंग के क्षेत्र में जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जिसमें ओरल कैंसर स्क्रीनिंग में शत प्रतिशत और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में 92 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने पॉजिटिव व संभावित मरीजों का व्यवस्थित डेटाबेस बनाकर नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक डेटा न देने वाले निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्री सिंह ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विकासखंडवार टॉप और बॉटम परफॉर्मिंग संस्थाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा एक सप्ताह के भीतर फील्ड स्तर पर सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन की समीक्षा भी की गई। खून की कमी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के निर्देश दिये गये।